भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2539
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

फर्जी मोबाइल कनेक्शन

2539. श्री विजय बघेल:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:
श्री शंकर लालवानी:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री नव चरण माझी:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किए गए या साइबर अपराध में शामिल मोबाइल कनेक्शनों की संख्या कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा काटे गए ऐसे मोबाइल कनेक्शनों की संख्या कितनी है जो जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे या साइबर अपराध में शामिल थे; और
- (ग) क्या सरकार ने सिम कार्ड हासिल करने के लिए केवाईसी प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता को बढ़ाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

- (क) और (ख) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नकली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त मोबाइल कनेक्शनों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल विकसित किया है और

विश्लेषण के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पुनः सत्यापन के बाद 78.33 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके अलावा, साइबर अपराध में शामिल होने की रिपोर्टिंग के आधार पर 6.78 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं।

(ग) ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए मौजूदा नो योर कस्टमर (केवाईसी) फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए दूरसंचार विभाग ने अब दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) {फ्रेंचाइजी, वितरक और एजेंट} जो ग्राहकों का नामांकन करते हैं और लाइसेंसधारियों की ओर से सिम जारी करते हैं का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अधिदेशित है.:

- i. प्रत्येक पीओएस का निर्विवाद सत्यापन;
- ii. पीओएस का बायोमेट्रिक सत्यापन;
- iii. पीओएस के व्यावसायिक और स्थानीय निवास के स्थान के पते का भौतिक सत्यापन;
- iv. जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में पीओएस का पुलिस सत्यापन;
- v. पीओएस के दायरे और कर्तव्यों, प्रचालन का क्षेत्र (एलएसए के भीतर सीमित), उल्लंघन के लिए करार की समाप्ति सहित दंडात्मक कार्रवाई से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों वाले पारस्परिक करारों पर हस्ताक्षर,;
- vi. यदि पीओएस द्वारा दिए गए दस्तावेज/जानकारी झूठे/जाली हों तब और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए)/एलएसए के निर्देशों पर सभी टीएसपी में पीओएस को ब्लैकलिस्ट करना;
- vii. ब्लैकलिस्टेड पीओएस द्वारा नामांकित सभी मोबाइल ग्राहकों का पुनः सत्यापन;
- viii. यदि कोई मौजूदा पीओएस दिनांक 31.01.2025 के बाद पंजीकरण के बिना ग्राहकों को नामांकित करता पाया जाता है तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में 10 लाख रुपये का जुर्माना; आदि।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने मौजूदा केवाईसी अनुदेशों में भी संशोधन किया है जिसमें पहले के थोक कनेक्शन फ्रेमवर्क को बंद करना और व्यावसायिक कनेक्शन फ्रेमवर्क की शुरुआत करना शामिल है जहां एक्टिवेशन से पहले प्रत्येक अंतिम-उपयोगकर्ता के केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (सिम) स्वैप/रिप्लेसमेंट के लिए एक मजबूत केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। कागजात आधारित केवाईसी प्रक्रिया को भी दिनांक 01.01.2024 से बंद कर दिया गया है।